सांध्य दैनिक
4PM
जिद...सच की
www.4pm.co.in www.facebook.com/4pmnewsnetwork @Editor_SanjayS YouTube @4pm NEWS NETWORK
● वर्ष: 12 ● अंक 190 पृष्ठ: 8 ● लखनऊ, सोमवार 17 अगस्त, 2026
मूल्य ₹ 3/-

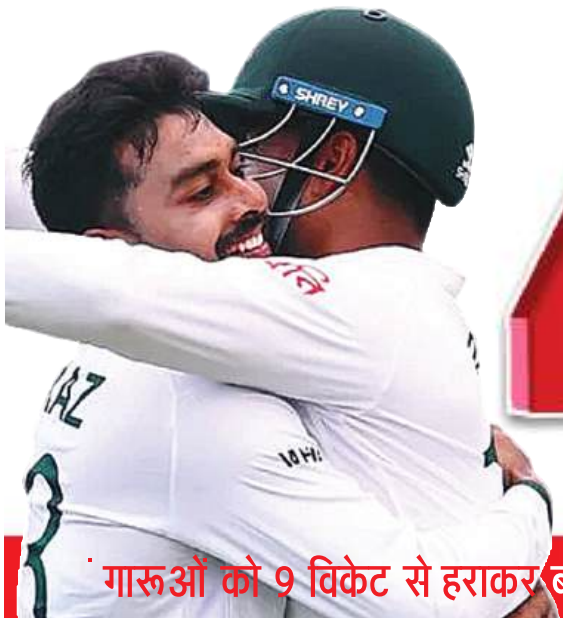

लोग अपने कर्तव्य भूल जाते हैं लेकिन अपने अधिकार उन्हें याद रहते हैं।

-इंदिरा गांधी

गारूओं को 9 विकेट से हराकर बांग्लादेश ने... 7 | मध्य प्रदेश में भाजपा व कांग्रेस... 3 | जो लोग बहुत ताकतवर थे, उन्हें... 2

क्या प्रधानमंत्री के दिमागी नक्सली बयान की छाया में रोक दी गई संजय शर्मा की 'सहिया'

जंगल में प्रेम की कहानी सेंसर के गलियारे में नक्सल का साया

» सहिया पर सेंसर का शिकंजा या नक्सल का बहाना?

» संजय शर्मा की सहिया पर सेंसर का ब्रेक कहानी प्रेम की सवाल नक्सल का

□□□ 4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

नई दिल्ली। संजय शर्मा की मूवी सहिया पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के एक बयान की काली छाया मंडराने लगी है। प्रेम पटकथा पर लिखी फिल्म सहिया को रिलीज की परमीशन में सेंसर बोर्ड की तरफ से देरी किया जाना शुरू हो गया है।

प्रोड्यूसर और डायरेक्टर संजय शर्मा ने फिल्म को सीबीएफसी दफ्तर में प्रायोरिटी कैटेगरी में सबमिट किया गया था लेकिन तय समय सीमा गुजर जाने के बाद भी फिल्म को रिलीज की परमीशन नहीं मिली इससे फिल्म के रिलीज प्लान पर असर पड़ रहा है और प्रोड्यूसर्स को फाइनेंशियल नुकसान हो रहा है। गौरतलब है कि 15 अगस्त को लाल किले से दिमागी नक्सल का नया नैरेटिव सामने आया है और ठीक उसी वक्त जंगल की पृष्ठभूमि पर बनी फिल्म सहिया को सीबीएफसी की स्क्रीनिंग में नक्सलवाद का संदर्भ दिखाई दे गया और फिल्म को स्क्रीनिंग कमेटी में भेजने की बात कही गयी है।

संजय शर्मा की पहली बड़ी फीचर फिल्म है सहिया

सहिया संजय शर्मा के लिए सिर्फ एक फिल्म नहीं है। वह इससे पहले दो शॉर्ट फिल्में बना चुके हैं। लेकिन यह उनकी पहली बड़ी फीचर फिल्म है। यानी एक नए फिल्मकार का सबसे बड़ा सपना अब रिलीज की प्रक्रिया में फंसा है। उन्होंने अपनी मेहनत पैसा और समय इस फिल्म में लगाया है। नेतरहाट के जंगलों में शूटिंग

हुई है। फिल्म में नीरज काबी, शांतनु माहेश्वरी और रिंकू राजगुरु जैसे कलाकार हैं। संगीत में सोना मोहपात्रा, जावेद अली, ऋचा शर्मा, कृष्णा बेउरा और स्वानंद किरकिरे जैसे नाम जुड़े हैं। गीत समीर अंजन और स्वानंद किरकिरे ने लिखे हैं। यानी यह कोई मोबाइल कैमरे से बनाई गई अचानक तैयार हुई फिल्म नहीं है। यह एक ऐसी परियोजना है जिसके पीछे लंबी तैयारी निवेश और पूरी टीम की मेहनत है और अब पूरी टीम एक सवाल के सामने खड़ी है कि फिल्म कब रिलीज होगी?

सहिया प्रेम की कहानी है

सहिया फिल्म की कहानी शुरू होती है जंगल से जहां न बंदूक है न बारूद न लाल झंडा। जहां नदी बहती है पेड़ों के बीच जिंदगी सांस लेती है और रिश्ते अपनी सबसे मासूम शक्ल में दिखाई देते हैं। कहानी प्रेम की है कहानी इंसान और इंसानियत की है कहानी प्रकृति और रिश्तों की है। लेकिन जैसे ही कहानी सेंसर बोर्ड के दरवाजे पर पहुंचती है अचानक उसके पीछे सेंसर बोर्ड को एक शब्द दिखाई देने लगता है नक्सलवाद। झारखंड के नेतरहाट के जंगलों में शूट हुई यह फिल्म अब रिलीज के इंतजार की लाइन में खड़ी है। फिल्म का नाम सहिया है और इसके निर्माता/निर्देशक हैं संजय शर्मा जिन्होंने अपनी पूंजी अपनी मेहनत और अपना भरोसा लगा कर इस फिल्म पर दांव पर लगाया है। फिल्म में कहानी प्रेम की है लेकिन सीबीएफसी के दरवाजे पर पहुंची तो सवाल नक्सलवाद का खड़ा हो गया। अब सवाल सिर्फ इतना नहीं कि सहिया को सर्टिफिकेट कब मिलेगा? बड़ा सवाल यह है कि क्या आज के राजनीतिक माहौल में नक्सल शब्द इतना संवेदनशील हो चुका है कि जंगल की पृष्ठभूमि में बनी प्रेम कहानी को भी संदेह की निगाह से देखा जाने लगे। और इससे भी बड़ा सवाल यह है कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वतंत्रता दिवस भाषण में इस्तेमाल किए गए दिमागी नक्सली जैसे राजनीतिक रूप से बेहद तीखे शब्दों के बाद नक्सलवाद से जुड़े किसी भी संदर्भ को देखने का नजरिया और ज्यादा कठोर हो जाए।

जंगल दिखना ही नक्सलवाद का संकेत कैसे

एक तरफ सीबीएफसी की अपनी वेबसाइट कहती है कि फिल्म प्रमाणन की प्रक्रिया तय चरणों और समय सीमाओं के भीतर होगी जबकि दूसरी तरफ प्रोड्यूसर और डायरेक्टर संजय शर्मा का कहना है कि प्रायोरिटी कैटेगरी के तहत आवेदन करने के बावजूद फिल्म की स्क्रीनिंग करीब डेढ़ महीने बाद हुई। स्क्रीनिंग के बाद बताया गया कि फिल्म की पृष्ठभूमि में नक्सलवाद का संदर्भ होने के कारण फिल्म को स्क्रीनिंग कमेटी में भेजा जाएगा। यहीं से सहिया की असली कहानी शुरू होती है। संजय शर्मा का कहना है फिल्म नक्सलवाद पर है ही नहीं तो फिर सवाल यह है कि जंगल दिखना ही नक्सलवाद का संकेत कैसे बन गया? क्या झारखंड के जंगलों में कहानी कहना भी अब एक राजनीतिक जोखिम है? क्या प्रकृति के बीच प्रेम की कहानी लिखने वाला फिल्मकार पहले यह प्रमाणपत्र लेकर आए कि उसकी कहानी में कोई वैचारिक बारूद नहीं है? या फिर सेंसर बोर्ड का काम यही है कि वह हर आशंका को गंभीरता से जांचे मगर जांच की प्रक्रिया भी उतनी ही पारदर्शी और समयबद्ध हो?

साहिया पूछ रही है जंगल दिखाना अपराध तो नहीं

और अब इस कहानी का सबसे बड़ा सवाल यह है कि भारत के जंगल सिर्फ भौगोलिक क्षेत्र नहीं हैं वह कहानियां हैं वह आदिवासी जीवन हैं वह प्रेम हैं वह लोकगीत हैं वह संघर्ष हैं वह प्रकृति हैं और हां वह नक्सलवाद से जुड़े सामाजिक राजनीतिक इतिहास के भी गवाह हैं। लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि जंगल की पृष्ठभूमि में बनी हर फिल्म को पहले नक्सलवाद के चश्मे से देखा जाएगा? अगर ऐसा नहीं है तो सहिया को लेकर यह सवाल उठा ही क्यों? और अगर ऐसा है तो फिर फिल्मकारों को पहले से पता होना चाहिए कि जंगल में कैमरा ले जाने से पहले उन्हें सिर्फ कहानी नहीं अपनी वैचारिक निर्दोषता भी साबित करनी होगी। यही वह सवाल है जो इस पूरी कहानी को सामान्य सेंसर विवाद से आगे ले जाता है।

जो लोग बहुत ताकतवर थे, उन्हें नौजवानों ने झुका दिया : अखिलेश यादव

सपा प्रमुख बोले- कार्यकर्ता कोई बयान न दें जिससे बीजेपी को लाभ मिले

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

लखनऊ । सपा अध्यक्ष ने भाजपा पर करारा प्रहार किया है। अखिलेश यादव ने अपने कार्यकर्ताओं से कहा है हमें ऐसा कोई बयान नहीं देना है, जिससे बीजेपी को लाभ मिले। कांग्रेस मुख्यालय पर वंदे मातरम को लेकर हुए विवाद पर बीजेपी पर निशाना साधा। सपा अध्यक्ष और पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने कहा है कि आजादी की लड़ाई में वीरांगना अवंती बाई लोधी ने वीरता और शौर्य के साथ अंग्रेजों का मुकाबला किया।

उन्होंने कहा कि जो लोग बहुत ताकतवर दिखाई दे रहे थे, उन्हें कम उम्र के नौजवानों और छात्रों ने झुका दिया। जो लोग रामराज लाने की बात करते थे, उन्होंने अयोध्या में राम धन लूट लिया। प्रभु श्रीराम मंदिर में चढ़ावा चोरी कर लिया। आलू व मक्का पैदा करने वाले किसानों को कीमत नहीं मिली। कन्नौज, फर्रुखाबाद, मैनपुरी और आसपास के जिलों में किसानों को भारी नुकसान हुआ। मुख्यमंत्री ने अपने जिले गोरखपुर में 500 प्राइमरी स्कूल बंद कर दिया।

भाजपा ने कभी तिरंगा नहीं फहराया

पूर्व सीएम ने कहा कि देश आजादी का जश्न मना रहा था और मुख्यमंत्री विभाजन का उत्सव मना रहे थे। भाजपा ने आजादी के पहले और आजादी के बाद कभी तिरंगा नहीं लगाया। लोधी समाज एकजुट हो गया तो भाजपा का पता नहीं चलेगा। समाजवादी पार्टी लोधी समाज को सम्मान और स्थान देगी। उन्होंने कहा कि 27 में भाजपा का सफाया होना तय है। 24 के परिणाम से समाजवादी पार्टी व इंडिया गठबंधन नंबर एक पर पहुंच गया है। उन्होंने तंज कसा कि इस सरकार में पायलट वनस्पति लेकर हवाई जहाज उड़ा रहे है। समाजवादी सरकार बनने के बाद तीन महीने में जातीय जनगणना कराकर सबको हक और सम्मान देंगे। वीरांगना अवंती बाई लोधी की जयंती कार्यक्रम में सांसद आरके चौधरी, पूर्व मंत्री अवधेश वर्मा आदि मौजूद रहे। कांग्रेस मुख्यालय पर वंदे मातरम को लेकर हुए विवाद पर बीजेपी पर निशाना साधा। अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा के पास दूसरा काम नहीं है। भाजपा पर कोई अच्छा काम होता तो वे संविधान को ठेस नहीं पहुंचाते।

गोमूत्र लेकर जाएंगे तो योजना बंद कर देगी सरकार

सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि एक तरफ सरकार 10 खरब डॉलर अर्थव्यवस्था की बात कर रही है, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि सरकार गोमूत्र खरीदेगी। जब लोग गोमूत्र लेकर जाएंगे तो सरकार योजना बंद कर देगी। एक तरफ एआई की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ गोमूत्र की, इनकी बातों पर कौन भरोसा करेगा।

सपा की सरकार बनी तो 16 अगस्त को होगी यूपी में छुट्टी

स्वतंत्रता आंदोलन में महारानी लक्ष्मी बाई के साथ ही हम वीरांगना अवंती बाई लोधी को भी याद करते है। समाजवादी सरकार में वीरांगना अवंती बाई लोधी के जन्म दिन पर 16 अगस्त को छुट्टी घोषित की जाएगी। 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के साथ ही 16 अगस्त को वीरांगना अवंती बाई लोधी को याद करने के लिए सरकारी छुट्टी होगी। गोमती रिवरफ्रंट पर वीरांगना अवंती बाई लोधी की प्रतिमा सोने की तलवार के साथ लगाकर सम्मान दिया जाएगा। खिलेश यादव ने इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान लखनऊ में वीरांगना महारानी अवंती बाई लोधी की 196वीं जयंती पर आयोजित विशाल सम्मेलन में उनकी प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर नमन किया। उन्होंने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। समाजवादी पार्टी को एक-एक वोट जोड़ना है। पीडीए में सभी लोगों को शामिल कर गुलदस्ता बनाया जाएगा। भाजपा सरकार को उत्तर प्रदेश में 10 वर्षों से देख रहे हैं। दिल्ली में भी कई वर्षों से भाजपा सरकार है।

अल्लाह के सिवा किसी की इबादत नहीं, ये मेरा संवैधानिक अधिकार : इमरान मसूद

वंदे मातरम विवाद पर बोले कांग्रेस सांसद

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

नई दिल्ली। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने सोमवार को कहा कि वह राष्ट्रगीत का सम्मान तो करेंगे, लेकिन उसे गाएंगे नहीं। उन्होंने इसके लिए अपने धर्म का पालन करने के संवैधानिक अधिकार का हवाला दिया। उनका यह बयान वंदे मातरम के गायन को लेकर मचे विवाद के बीच आया है, जिसमें पार्टी आलाकमान सोनिया गांधी, राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खरगे भी शामिल रहे हैं।

वंदे मातरम विवाद पर बात करते हुए मसूद ने कहा कि मैं अल्लाह के अलावा किसी और की इबादत नहीं कर सकता। यह अधिकार मुझे संविधान ने दिया है। आप मुझसे यह अधिकार छीन नहीं सकते। लेकिन, मैं इसका (वंदे मातरम का) अपमान नहीं करूंगा। मैं इसे गाऊंगा नहीं, लेकिन इसके सम्मान में खड़ा जरूर होऊंगा। कांग्रेस सांसद ने कहा कि उन्होंने कभी वंदे मातरम नहीं गाया है और भविष्य में भी ऐसा

नहीं करेंगे, लेकिन जब इसे गाया जाएगा तो वह खड़े जरूर होंगे। मसूद ने कहा कि अगर आप चाहें तो वंदे मातरम को बढ़ावा दें। इससे मुझे क्या फ़र्क पड़ता है? मैं उतना ही करूंगा जितना मैं चाहता हूं, और वही करूंगा। मैंने इसे पहले कभी नहीं गाया है और न ही भविष्य में गाऊंगा। मैं बस खड़ा हो जाऊंगा। मुझे अपने धर्म का पालन करने का संवैधानिक अधिकार है। पहले वंदे मातरम का पूरा इतिहास पढ़ें। फिर आकर मुझसे बात करें। पढ़ें कि यह कहाँ से आया, इसे कैसे लिखा गया और क्यों लिखा गया।

यह बयान तब आया जब भाजपा ने वंदे मातरम विवाद को लेकर कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी के ख़िलाफ़ शिकायत दर्ज कराई। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में एक रैली को संबोधित करते हुए, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आरोप लगाया कि शनिवार को कांग्रेस मुख्यालय में वंदे मातरम गाए जाने के दौरान सोनिया ने पार्टी कार्यकर्ताओं से इसे रोकने के लिए कहा था। शाह ने कहा कि उनकी (कांग्रेस की) बेशर्मी देखिए। कांग्रेस पार्टी मुख्यालय में राष्ट्रगीत %वंदे मातरम गाया जा रहा था। राष्ट्रगीत के दौरान, कांग्रेस नेता सोनिया गांधी ने कांग्रेस अध्यक्ष से गाना रोकने के लिए कहा। हम सब बस टीवी पर देखते रह गए। उन्होंने सीधे सोनिया गांधी को संबोधित करते हुए कहा कि सोनिया जी, 140 करोड़ लोग आपको देख रहे हैं। आपने जो पाप किया है, उसे देश की जनता कभी माफ़ नहीं करेगी। सोनिया गांधी ने पहले ही साफ़ कर दिया था कि वह कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के लिए कुर्सी मांग रही थीं और वंदे मातरम के गायन को रोकने का उनका कोई इरादा नहीं था।

एक ही परिवार के तीन लोगों सहित चार कांवड़िया गंगा में डूबे

तलाश में जुटी एनडीआरफ व गोताखोर

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

फर्रुखाबाद। शहर के पांचाल घाट पर सोमवार को भोर में जल भरने से पहले स्नान के दौरान एक ही परिवार के तीन लोगों सहित एक ही गांव चार लोग गंगा में डूब गए। पुलिस स्थानीय गोताखोरों के साथ एनडीआरफ उनकी तलाश में जुटी है। पानी का बहाव तेज होने से दोपहर तक उनका पता नहीं चला। शाहजहांपुर जनपद के नयागांव खुदागंज निवासी योगेश (17) पुत्र प्रमोद सक्सेना अपने चाचा विकास (25) पुत्र सोनपाल सक्सेना व चचेरे चाचा कमल (23) पुत्र सत्यपाल व गांव के अर्जुन (17) पुत्र राजेश प्रजापति के अलावा सहित दस लोगों के साथ कांवड़ लेकर पांचाल घाट रविवार देर रात पांच बाइकों से पहुंचे थे।

सोमवार भोर में करीब 4.30 बजे पांचाल घाट के उत्तरी बंधा के पास स्नान करने पहुंचे। वहां इनके साथी बाइकों के पास खड़े हो गए। बाकी लोगों गंगा में स्नान करने लगे। योगेश सहित चारों लोग गहरे पानी में जाने लगे तभी बाहर खड़े उनके

साथियों व पुलिस कर्मियों ने उन्हें मना किया पर वह नहीं माने और गहरे पानी में चले गए। देखते ही देखते चारों गोते खाने लगे। यह देख वहां स्नान कर रहे लोगों ने शोर मचाया लेकिन कुछ ही देर में चारों डूब गए और लापता हो गए। इसकी जानकारी मिलते ही पुलिस अधीक्षक आरती सिंह मौके पर पहुंच गईं। उन्होंने एनडीआरएफ के साथ स्थानीय गोताखोरों को भी उनकी तलाश में लगा दिया। जानकारी मिलने पर परिजन पांचाल घाट पहुंच गए। योगेश हाईस्कूल का छात्र था।

बामुलाहिजा

कार्टून: हसन जैदी

जब पुलिस सुरक्षित नहीं तो आमजन का क्या होगा : मायावती

आईएएस अफसर की मां की हत्या पर भड़कीं बसपा प्रमुख

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के अम्बेडकरनगर जिले से एक बेहद दुखद और सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहां वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी आशुतोष मिश्रा की 91 वर्षीय बुजुर्ग मां की जघन्य हत्या कर दी गई। इस वारदात के बाद बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने राज्य की कानून-व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं।

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इस घटना की कड़ी निंदा करते हुए मायावती ने लिखा कि यूपी के अम्बेडकरनगर जिले में वरिष्ठ आईपीएस अफसर आशुतोष मिश्रा की लगभग

91-वर्षीय बुजुर्ग माता की हुई हत्या अति-दुखद है। उन्होंने इस वारदात को प्रदेश में बिगड़ती कानून-व्यवस्था के हिसाब से अति-चिन्तनीय बताया।

दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग

बसपा सुप्रीमो ने राज्य सरकार से इस पूरे मामले में तुरंत और कड़ा कदम उठाने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि सरकार को इस घटना का उचित संज्ञान लेना चाहिए और वारदात में शामिल दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए, जो कि बेहद जरूरी है।

मायावती ने सरकार और प्रशासन की सुरक्षा व्यवस्था पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि ऐसी घटना को लेकर आम लोगों की यह आशंका पूरी तरह से वाजिब है कि जब हत्या जैसी जघन्य वारदात किसी बड़े पुलिस अधिकारी के परिवार के साथ हो सकती है, तो आम जनता की सुरक्षा का क्या होगा?

मध्य प्रदेश में भाजपा व कांग्रेस संगठन में हलचल बढ़ी

दतिया उपचुनाव के परिणाम का असर

राहुल गांधी के दौरे से मालवा-निमाड़ में बढ़ेगा उत्साह

- महाकाल की नगरी में गूंजेगा कांग्रेस का शंखनाद
- भाजपा की टीम नवीन की सुगबुगाहट तेज
- एमपी के चार चेहरों पर नजर

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

उज्जैन। मप्र में हुए उपचुनाव दतिया में कांग्रेस जीत से उत्साहित है तो वहीं भाजपा आहत है। जोश से भरी राज्य कांग्रेस फिर उर्जा भरने की रणनीति पर काम करने जा रही है। वहीं भाजपा अपने संगठन में मजबूती के लिए कदम उठाने की योजना बना रही है। दोनों की रणनीति कितनी कारगर होती है ये तो आने वाले चुनावों के परिणाम ही बताएंगे।

इसी क्रम में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का सितंबर में उज्जैन दौरा प्रस्तावित है। वे बाबा महाकाल के दर्शन के बाद कांग्रेस के संगठन सृजन अभियान के तहत कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे। उज्जैन संभाग के हजारों पदाधिकारी शामिल होंगे। दौरे की आधिकारिक तारीख घोषित नहीं हुई है। कार्यक्रम के लिए कार्तिक मेला ग्राउंड विकल्प है। उधर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की नई टीम के गठन की तैयारी के बीच मध्यप्रदेश से राष्ट्रीय संगठन में जगह पाने वाले नेताओं के नामों पर चर्चा तेज हो गई है। वीडी शर्मा, कविता पाटीदार, गजेंद्र पटेल और लालसिंह आर्य संभावित चेहरों में शामिल हैं।

भव्य संवाद कार्यक्रम में हजारों पदाधिकारी और कार्यकर्ता शिरकत करेंगे

इस भव्य संवाद कार्यक्रम में उज्जैन संभाग के विभिन्न जिलों रतलाम, देवास, शाजापुर, आगर मालवा, मंदसौर और नीमच के हजारों पदाधिकारी और कार्यकर्ता शिरकत करेंगे। राहुल गांधी जिला व ब्लॉक अध्यक्षों के साथ-साथ मंडल, ग्राम पंचायत अध्यक्षों और बीएलए-2 स्तर के समर्पित कार्यकर्ताओं से सीधे रूबरू होकर बूथ स्तर की वास्तविक स्थिति, संगठन की सक्रियता और आगामी राजनीतिक रणनीतियों पर फीडबैक लेंगे। इस प्रस्तावित दौरे की आधिकारिक तारीखों का ऐलान होना अभी बाकी है, लेकिन उज्जैन में कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। कार्यक्रम और संभावित जनसभा के लिए उज्जैन के कार्तिक मेला ग्राउंड को विकल्पों के रूप में देखा जा रहा है। नगर निगम में प्रतिपक्ष के नेता रवि राय सहित वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं का कहना है कि आधिकारिक घोषणा से पहले ही संगठन के हर स्तर पर व्यवस्थाएं दुरुस्त की जा रही हैं। उज्जैन के इस बड़े आयोजन के सफल समापन के बाद इसी तर्ज पर रीवा संभाग में भी कार्यकर्ता संवाद कार्यक्रम आयोजित करने की योजना है। इससे पहले राहुल गांधी 5 मार्च 2024 को अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान महाकालेश्वर मंदिर आए थे। माना जा रहा है कि बाबा महाकाल के आशीर्वाद और राहुल गांधी के इस सीधे संवाद से मालवा की धरा पर कांग्रेस संगठन में एक नई क्रांति और अटूट ऊर्जा का संचार होगा।

कांग्रेसियों में ऊर्जा और उत्साह की नई लहर दौड़ी

बाबा महाकाल की पावन नगरी उज्जैन जल्द ही एक बड़े राष्ट्रीय राजनीतिक घटनाक्रम की साक्षी बनने जा रही है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का बहुप्रतीक्षित उज्जैन दौरा सितंबर में प्रस्तावित है, जिसे लेकर पूरे मालवा और निमाड़ अंचल के कांग्रेसियों में ऊर्जा और उत्साह की नई लहर दौड़ गई है। राहुल गांधी अपने इस दौरे की शुरुआत विश्वह्प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग बाबा महाकाल के दर पर मत्था टेककर आशीर्वाद लेने के साथ करेंगे। उज्जैन नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष रवि राय ने बताया कि यह दौरा महज एक औपचारिक यात्रा न होकर मध्य प्रदेश में कांग्रेस को जमीनी स्तर पर पुनर्जीवित करने और संगठन को बूथ स्तर तक नई धार देने का बड़ा जरिया बनने जा रहा है। दौरे की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें केवल बड़े नेताओं का जमघट नहीं होगा, बल्कि संगठन सृजन अभियान के तहत राहुल गांधी सीधे जमीनी सिपाहियों और कार्यकर्ताओं से संवाद कर संगठन की वास्तविक नब्ज टटोलेंगे।

पीएम से मुलाकात के बाद चर्चा तेज

पूर्व प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीडी शर्मा का नाम संभावित दावेदारों में सबसे प्रमुख माना जा रहा है। वे लंबे समय तक मध्यप्रदेश भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं और संगठन को बूथ स्तर से लेकर चुनावी प्रबंधन तक संभालने का अनुभव रखते हैं। प्रदेश में भाजपा को लगातार मजबूत करने के दौर में उनकी भूमिका महत्वपूर्ण रही है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनकी मुलाकात ने भी उनके अगले राजनीतिक कदम को लेकर चर्चाओं को हवा दी है। वीडी शर्मा के पक्ष में ब्राह्मण प्रतिनिधित्व के साथ संगठनात्मक अनुभव भी जाता है। यदि भाजपा राष्ट्रीय टीम में अनुभवी और संगठन को समझने वाले नेताओं को बड़ी भूमिका देने की रणनीति अपनाती है, तो उनका नाम मजबूत दावेदारों में रह सकता है।

महिला और ओबीसी का समीकरण पर नजर

राज्यसभा सांसद कविता पाटीदार भी राष्ट्रीय संगठन के लिए संभावित चेहरों में हैं। प्रदेश भाजपा संगठन में महामंत्री की जिम्मेदारी संभाल चुकी पाटीदार के पास संगठन के साथ संसदीय राजनीति का अनुभव भी है। उनके नाम के साथ महिला और ओबीसी दोनों समीकरण जुड़ते हैं। भाजपा के लिए महिला मतदाताओं की बढ़ती राजनीतिक भूमिका को देखते हुए राष्ट्रीय टीम में किसी महिला नेता को प्रमुख जिम्मेदारी देना महत्वपूर्ण संदेश हो सकता है। वहीं ओबीसी प्रतिनिधित्व के लिहाज से भी उनका नाम पार्टी के सामाजिक विस्तार की रणनीति में फिट बैठता है।

भाजपा सरकार पिछले 22 सालों में किए गए वादों को पूरा करने में नाकाम रही : सिंघार

मध्य प्रदेश विधानसभा में विपक्ष के नेता उमंग सिंघार ने दतिया उपचुनाव में कांग्रेस की जीत का स्वागत करते हुए कहा था कि बीजेपी पिछले दो दशकों में अपने वादे पूरे करने में नाकाम रही है। कांग्रेस उम्मीदवार घनश्याम सिंह ने बीजेपी के आशुतोष तिवारी को 6016 वोटों के अंतर से हराया। उमंग सिंघार ने इस जीत का कारण किसानों और युवाओं के कल्याण की कमी और दलितों व आदिवासियों पर हो रहे अत्याचारों को बताया। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश की जनता बदलाव चाहती है। कांग्रेस नेता ने कहा

कि अगर मध्य प्रदेश की बात करें, तो सरकार पिछले 22 सालों में किए गए वादों को पूरा करने में नाकाम रही है। आज भी किसानों को खाद नहीं मिल रही है और युवाओं को रोज़गार नहीं मिल रहा है। दलितों और आदिवासियों को अपनी जमीन पर भारी अत्याचार का सामना करना पड़ रहा है। जनता के पैसे और टैक्स देने वालों के पैसे का गलत इस्तेमाल हो रहा है। आपने बिहार में भी ऐसी ही स्थिति देखी थी। देश और राज्य की जनता अब बदलाव चाहती है। वहीं सपा नेता धर्मेंद्र यादव ने कहा कि यह तो बस शुरुआत है। दतिया और बांकीपुर के लोगों ने दिखा दिया है कि वे क्या देख रहे हैं और भाजपा का कितना विरोध है। जिस तरह से बेटियों का अपमान हुआ है, जिस तरह से पटना के गांधी मैदान में विरोध कर रहे युवाओं के साथ अन्याय और अत्याचार हुआ है... बिहार के लोग बहुत जागरूक हैं।

पीएम मोदी से मिले पूर्व प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीडी शर्मा

भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की नई टीम के गठन की कवायद के बीच मध्य प्रदेश से भी राष्ट्रीय संगठन में जगह पाने वाले संभावित चेहरों को लेकर चर्चा तेज हो गई है। खास बात यह है कि पूर्व प्रदेश भाजपा अध्यक्ष और सांसद विष्णुदत्त शर्मा (वीडी शर्मा) की हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हुई मुलाकात के बाद उनके नाम को लेकर राजनीतिक हलकों में अटकलें और तेज हुई हैं। भाजपा के सामने राष्ट्रीय टीम में नए चेहरों को जगह देने के साथ सामाजिक और क्षेत्रीय संतुलन साधने की चुनौती है। ऐसे में मध्यप्रदेश से ब्राह्मण, ओबीसी, दलित और आदिवासी वर्ग के चेहरों को प्रतिनिधित्व देने पर विचार हो सकता है। संभावित नामों में वीडी शर्मा, राज्यसभा सांसद कविता पाटीदार, सांसद गजेंद्र पटेल और वरिष्ठ नेता लालसिंह आर्य की चर्चा है। हालांकि, अंतिम निर्णय केंद्रीय नेतृत्व ही करेगा और इसमें जातीय समीकरण के अलावा संगठन में पकड़, चुनावी प्रबंधन, अनुभव और राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकार्यता अहम होगी।

Sanjay Sharma

editor.sanjaysharma
@Editor_Sanjay

जिद... सच की

खेलों में और सुविधाएं बढ़ाई जाएं

अभी हाल में ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेल में भारत का प्रदर्शन उम्मीद से कहीं बेहतर रहा। भारत सन 2000 के बाद खेलों में उम्दा प्रदर्शन कर रहा है। पिछले 26 सालों में खेल की दुनिया में भारत के खिलाड़ियों ने बहुत नाम कमाया है। कु छ विवादों को छोड़कर ओवरआल हमारे खिलाड़ी दुनिया को मात दे रहे हैं। खिलाड़ियों को कु छ और सुविधाएं बढ़ा दी जाएं तो वह और उम्दा कर सकते हैं। कि के ट के अतिरिक्तअन्य खेलों में इनका प्रदर्शन बढ़िया है। अभी हाल में ग्लासगो में भारत ने 13 स्वर्ण, 17 रजत और 9 कांस्य सहित कुल 39 पदक जीते। वह पदक तालिका में चौथे नंबर पर रहा। पहली नजर में यह प्रदर्शन बर्मिंघम 2022 के 61 पदक से कमजोर दिख सकता है, लेकिन आंकड़े अलग कहानी बताते हैं। इस बार ग्लासगो में सिर्फ 10 खेल शामिल थे, जबकि बर्मिंघम में 19 खेल खेले गए थे। बैडमिंटन, कुश्ती, शूटिंग, हॉकी, टेबल टेनिस और क्रिकेट जैसे खेल ग्लासगो गेम्स का हिस्सा नहीं थे, जिनसे 2022 में भारत को 30 पदक मिले थे। इसके अलावा भारत ने 210 खिलाड़ियों की जगह सिर्फ 123 खिलाड़ियों का दल भेजा। इनमें से 38 खिलाड़ी पदक जीतकर लौटे, यानी सफलता की दर 31 प्रतिशत रही। बर्मिंघम में यह आंकड़ा 29 प्रतिशत था।

ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेल शुरू होने से पहले भारतीय ओलंपिक संघ और विभिन्न खेल महासंघों की आंतरिक रिपोर्ट में भारत को 6 स्वर्ण समेत 31 पदक मिलने का अनुमान लगाया गया था। भारतीय खिलाड़ियों ने अनुमान से दोगुना से भी ज्यादा स्वर्ण जीते। कुल पदक में भी आगे निकल गए। ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेल में भारत का सबसे सफल खेल बॉक्सिंग रहा। 14 मुक्के बाजों के दल में से 10 खिलाड़ी पदक जीतकर लौटे। इसमें 7 स्वर्ण और 3 रजत शामिल रहे। यानी 71 प्रतिशत मेडल कन्वर्जन रेट। बर्मिंघम 2022 में यह आंकड़ा 58 प्रतिशत था। पदक वितरण समारोह के दौरान सात बार भारत का राष्ट्रगान बजना न सिर्फ ग्लासगो में मौजूद भारतीय दर्शकों के लिए गर्व का पल था, बल्कि इस बात का सबूत भी था कि इस गैर-पारंपरिक खेल को गांवों और छोटे कस्बों तक ले जाने की पहल काफी हद तक सफल रही है। भारतीय बॉक्सरों के प्रदर्शन की जितनी भी प्रशंसा की जाए वो कम है। जूडो में भारत ने पहली बार राष्ट्रमंडल खेल इतिहास में स्वर्ण जीता। अस्मिता डे और हर्ष सिंह ने स्वर्ण जीता। यामिनी मौर्य ने रजत और उन्नति शर्मा ने कांस्य जीतकर कुल चार पदक भारत की झोली में डाले। हालांकि 14 सदस्यीय भारतीय टीम के दो खिलाड़ी अरुण कुमार और तुलिका मान डोपिंग के कारण बाहर हो गए। इसी तरह, एथलीटों और पैरा-एथलीटों ने 16 पदक जीते। इनमें से कुछ ने तो नए राष्ट्रीय रिकॉर्ड भी बनाए।

“ इस बार ग्लासगो में सिर्फ 10 खेल शामिल थे, जबकि बर्मिंघम में 19 खेल खेले गए थे। बैडमिंटन, कुश्ती, शूटिंग, हॉकी, टेबल टेनिस और क्रिकेट जैसे खेल ग्लासगो गेम्स का हिस्सा नहीं थे, जिनसे 2022 में भारत को 3० पदक मिले थे।

(इस लेख पर आप अपनी राय 9559286005 पर एसएमएस या info@4pm.co.in पर ई-मेल भी कर सकते हैं)

डिजिटल मोह में बौद्धिक पूंजी की अनदेखी

चंद्रशेखर तिवारी

किसी भी समाज और राष्ट्र की बौद्धिक समृद्धि का आकलन केवल उसके विद्यालयों, महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों की संख्या से नहीं किया जा सकता, बल्कि यह इस बात से तय होता है कि वहां पुस्तकें कितनी पढ़ी जाती हैं और पुस्तकालय कितने जीवंत हैं। पुस्तकालय केवल किसी भवन में रखी पुस्तकों का संग्रह मात्र नहीं होते, बल्कि वे ज्ञान, विचार, संवाद, संस्कृति और लोकतांत्रिक चेतना के अत्यंत महत्वपूर्ण केंद्र होते हैं। आज के डिजिटल युग में, हालांकि सार्वजनिक पुस्तकालयों की संख्या लाखों में है, लेकिन उनमें पाठकों की लगातार घटती संख्या एक गंभीर चिंता का विषय बन गई है। यदि आंकड़ों पर नजर डालें, तो संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत राजा राममोहन राय पुस्तकालय प्रतिष्ठान के अनुसार देश में 46,746 से अधिक सार्वजनिक पुस्तकालय हैं।

इनमें महाराष्ट्र, केरल, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु जैसे राज्यों में इनकी बड़ी संख्या है। इसके अलावा शैक्षणिक संस्थानों के पुस्तकालयों को मिला दिया जाए तो यह संख्या और भी बढ़ जाती है। परंतु, केवल आंकड़ों का यह विस्तार पुस्तकालयों की गुणवत्ता और वास्तविक उपयोगिता की गारंटी नहीं देता है। आज देश के अधिकांश सार्वजनिक पुस्तकालय सीमित बजट, पुरानी पुस्तकों, जर्जर भवनों, तकनीकी सुविधाओं की कमी और प्रशिक्षित कर्मचारियों के अभाव जैसी गंभीर समस्याओं से जूझ रहे हैं। कई स्थानों पर पुस्तकालयाध्यक्ष के पद वर्षों से रिक्त पड़े हैं, और पुस्तकालयों के खुलने-बंद होने का समय भी आम नागरिकों या नौकरीपेशा लोगों की सुविधा के अनुकूल नहीं होता। इसके अलावा, दिव्यांगों, बच्चों और वरिष्ठ नागरिकों के लिए जरूरी सुविधाओं का अभाव भी पाठकों को इन संस्थानों से दूर कर रहा है। हालांकि, यह मान लेना बिल्कुल गलत होगा कि भारतीय समाज में पढ़ने की इच्छा समाप्त हो गई है। एनसीईआरटी, नेशनल बुक ट्रस्ट और विभिन्न अध्ययनों से यह स्पष्ट होता है कि पढ़ने की प्रवृत्ति आज भी मौजूद है, लेकिन उसका माध्यम और तरीका बदल चुका है।

मोबाइल फोन, इंटरनेट और सोशल मीडिया के दौर में युवा डिजिटल सामग्री तो बड़े पैमाने पर पढ़ रहे हैं, लेकिन लंबे समय तक किसी पुस्तक को एकाग्र होकर पढ़ने और उस पर विचार करने की आदत कमजोर हुई है। त्वरित सूचना और मनोरंजन की संस्कृति के बीच एकाग्रता के लिए समय निकालना कठिन होता जा रहा है। समस्या की जड़ यह है कि यदि पुस्तकालय में पाठक की जरूरत के अनुरूप आधुनिक पुस्तकें, हाई-स्पीड

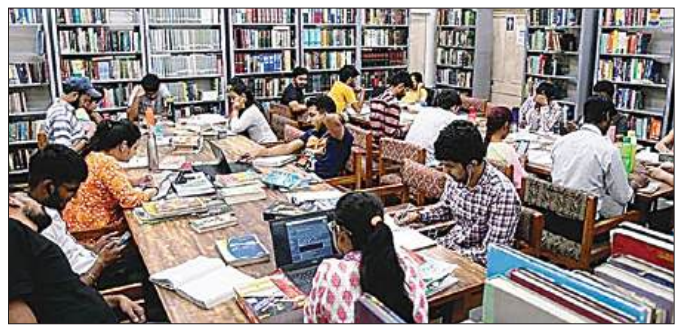

इंटरनेट, शांत वातावरण और सामुदायिक गतिविधियां नहीं होंगी, तो पाठक वहां क्यों जाएगा? एक आधुनिक पुस्तकालय में मुद्रित पुस्तकों के साथ-साथ ई-बुक्स, ऑडियो बुक्स, डिजिटल अभिलेखागार, ऑनलाइन कैटलॉग और दूरस्थ डिजिटल अध्ययन की सुविधा भी होनी चाहिए। डिजिटल तकनीक पुस्तकालयों के लिए चुनौती जरूर है, लेकिन यह उनके विस्तार का सबसे बड़ा अवसर भी है। इन चुनौतियों से पार पाने के लिए पुस्तकालयों के प्रति दृष्टिकोण को बदलना होगा। पुस्तकालयों के बजट को अक्सर गैर-जरूरी खर्च मान लिया जाता है, जबकि सड़क, अस्पताल और विद्यालयों की तरह पुस्तकालय भी बुनियादी सार्वजनिक संस्थान हैं, जिनका प्रभाव व्यक्ति और समाज के दीर्घकालिक विकास पर पड़ता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 और 'नेशनल मिशन ऑन लाइब्रेरीज' जैसी पहलों ने इस दिशा में सकारात्मक कदम उठाए हैं, लेकिन इनकी सफलता के लिए राज्यों में पर्याप्त बजट, स्पष्ट नीति और एक मजबूत पुस्तकालय कानून का होना अनिवार्य है। पुस्तकालयों को स्थानीय समाज की गतिविधियों का जीवंत केंद्र बनाना होगा। पुस्तक चर्चा, लेखक से संवाद, कहानी सत्र, कविता पाठ, विज्ञान क्लब, स्थानीय इतिहास पर व्याख्यान, डिजिटल साक्षरता और युवा नवाचार मंच जैसी पहलें पुस्तकालयों में जान फूंक सकती हैं। देहरादून का 'दून पुस्तकालय एवं शोध केन्द्र' इसका एक बेहतरीन उदाहरण है, जहां सांस्कृतिक कार्यक्रमों, गोष्ठियों और संवादों के जरिए पुस्तकालय को एक जीवंत सांस्कृतिक केंद्र के रूप में विकसित किया गया है। नि:संदेह, पढ़ने की आदत बचपन से ही विकसित होती है। यदि घर और विद्यालय में पढ़ने का अनुकूल वातावरण मिले, तो बच्चों में कल्पनाशीलता, संवेदनशीलता और स्वतंत्र चिंतन का विकास होता है।

इसके साथ ही, मुद्रित पुस्तकों और डिजिटल सामग्री को एक-दूसरे का पूरक बनाकर स्थानीय इतिहास और लोक साहित्य का डिजिटलीकरण करना पुस्तकालयों को एक नई प्रासंगिकता दे सकता है। अंतत:, सार्वजनिक पुस्तकालय किसी भी देश की वास्तविक बौद्धिक पूंजी हैं। इन्हें मजबूत करना केवल पुरानी पुस्तकों की रक्षा करना नहीं, बल्कि पठन संस्कृति, स्वतंत्र चिंतन और एक स्वस्थ लोकतांत्रिक समाज के भविष्य को सुरक्षित करना है।

समझौता संस्कृति में घुटती बेटियों की सांसें

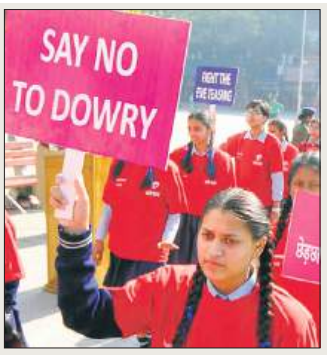

डॉ. रितु सारस्वत

हाल ही में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने 'दिनेश कुमार एवं अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य' तथा 'श्रीमती बिट्टा देवी एवं अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य' वाद में निर्णय देते हुए कहा 'दहेज उत्पीड़न की लगातार शिकायतों के बावजूद किसी विवाहित महिला को 'समझौता करने', 'समायोजन करने' अथवा 'विवाह बचाने' की सलाह देना कई बार उत्पीड़कों का मनोबल बढ़ा देती है और उसके परिणाम दुखद तथा घातक हो सकते हैं।' इतना ही नहीं, न्यायालय ने यह भी कहा कि किसी विवाहित बेटी द्वारा बार-बार की गई शिकायतों को सामान्य वैवाहिक असहमति नहीं, बल्कि 'सहायता, संरक्षण और समय पर हस्तक्षेप की वास्तविक पुकार' के रूप में देखा जाना चाहिए। न्यायालय ने स्पष्ट रूप से रेखांकित किया कि 'परिवार का नैतिक और सामाजिक दायित्व है कि वह बेटी की बात पर विश्वास करे, उसका साथ दे तथा उसकी सुरक्षा और गरिमा सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठाए।'

वस्तुत: न्यायालय की ये टिप्पणियां केवल एक आपराधिक वाद के निस्तारण तक सीमित नहीं हैं, बल्कि भारतीय समाज की उस गहरी सामाजिक मानसिकता पर गंभीर प्रश्नचिह्न हैं, जहां अनेक बार बेटी को अपनी पीड़ा, अपमान और प्रताड़ना की अवहेलना करने और हर स्थिति में विवाह बनाए रखने के लिए विवश किया जाता है। यह पहली बार नहीं है कि न्यायपालिका ने बेटियों की सुरक्षा, सम्मान और गरिमा को लेकर चिंता व्यक्त की हो। इससे पूर्व वर्ष 2005 में 'इन री एनफोर्समेंट एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दहेज प्रोहिबिशन एक्ट, 1961' वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था 'समाज की चेतना दहेज प्रथा जैसी बुराई के प्रति इस स्तर तक जाग्रत होनी चाहिए कि दहेज मांगना ही समाज में अपमान का कारण बन जाए। हमें पूर्ण विश्वास है कि हमारी युवा और जागरूक महिलाएं इस सामाजिक बुराई का डटकर सामना करेंगी, जो उन्हें व्यापार की वस्तु बना देती है।

हमें यह भी आशा है कि हमारे शिक्षित युवा स्वयं को विवाह के बाजार में बिकने से इंकार करेंगे और निष्पक्ष एवं सम्मानजनक आधार पर अपने जीवनसाथी का चयन करेंगे।' दुर्भाग्यवश, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह आशा व्यक्त किए जाने के 21 वर्ष बाद भी समाज की चेतना में अपेक्षित परिवर्तन परिलक्षित नहीं होता। यक्ष प्रश्न यह है कि भारतीय समाज में ऐसी सामाजिक मानसिकता का निर्माण आखिर हुआ कैसे, जहां किसी विवाहित बेटी द्वारा बार-बार सहायता की गुहार लगाने के बाद भी उसे सबसे पहले 'समझौता' करने की सलाह दी जाती है? यदि अधिकांश मामलों में पीड़िता अपनी व्यथा पहले ही अपने परिवार के समक्ष व्यक्त कर चुकी होती है, तो फिर प्रत्येक त्रासदी के बाद यह प्रश्न क्यों उठता है कि उसने शिकायत क्यों नहीं की? वास्तविकता यह है कि अनेक बार उसकी पीड़ा को गंभीरता से लेने के बजाय सामान्य वैवाहिक विवाद मानकर टाल दिया जाता है। वस्तुत: समस्या कानून के अभाव की नहीं, बल्कि उस सामाजिक संस्कृति की है, जिसने वर्षों से 'समझौता कर लो' को सामाजिक मानक बना दिया है। शहाना रसूल ने अपने शोधपत्र द इन्फ्लुएंस ऑफ सोशल कन्स्ट्रक्शन्स ऑफ फैमिली ऑन एब्यूज्ड विमेन्स हेल्प-सीकिंग आफ्टर डोमेस्टिक वायलेंस में भी इसी सामाजिक प्रवृत्ति की ओर संकेत किया है।

उनके अनुसार अनेक महिलाएं हिंसक वैवाहिक संबंधों में इसलिए बनी रहती हैं क्योंकि परिवार और समाज उनसे संबंध समाप्त करने के बजाय उसे हर परिस्थिति में बनाए रखने की अपेक्षा करते हैं। परिणामस्वरूप सहायता की अपेक्षा लेकर की गई उनकी पहल भी अनेक बार इस सामाजिक आग्रह के आगे ठहर जाती है कि 'विवाह हर परिस्थिति में बनाए रखा जाए।' निश्चित रूप से कोई भी वैवाहिक जीवन समझौते, पारस्परिक सहयोग और संवेदनशीलता के बिना नहीं चल सकता। परंतु यह भी उतना ही आवश्यक है कि समाज समझौते और अत्याचार के बीच स्पष्ट सीमा-रेखा निर्धारित करना सीखे। यदि किसी स्त्री को निरंतर अपमानित किया जा रहा हो, उसके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाई जा रही हो, मानसिक अथवा शारीरिक प्रताड़ना दी जा रही हो और 'भय' और 'प्रताड़ना' उसके दैनिक जीवन का हिस्सा बन चुका हो, तो उसे समझौता नहीं, बल्कि अत्याचार कहा जाएगा। दुर्भाग्यवश, हमारे समाज ने 'समझौता' शब्द की परिधि इतनी व्यापक कर दी है कि अनेक बार हिंसा और उत्पीड़न भी उसी के भीतर समाहित कर दिए जाते हैं। निस्संदेह विवाह एक महत्वपूर्ण सामाजिक संस्था है, परंतु किसी भी सामाजिक संस्था का मूल्य किसी व्यक्ति के जीवन, सुरक्षा और गरिमा से अधिक नहीं हो सकता।

दुर्भाग्यवश, आज भी अनेक परिवार अपनी बेटियों के 'सफल वैवाहिक जीवन' को एक ऐसी सामाजिक उपलब्धि के रूप में देखते हैं, जिसे हर परिस्थिति में बनाए रखना आवश्यक समझा जाता है। यही कारण है कि अनेक बार बेटी की सुरक्षा से अधिक विवाह की निरंतरता चिंता का विषय बन जाती है। जबकि किसी भी वैवाहिक संबंध की सफलता का मापदंड केवल उसका लंबे समय तक चलना नहीं, बल्कि उसमें निहित पारस्परिक सम्मान, सुरक्षा, विश्वास और गरिमा भी होना चाहिए। वास्तव में सबसे बड़ी विडंबना यह है कि जिस सामाजिक प्रतिष्ठा की रक्षा के लिए अनेक परिवार अपनी बेटियों को हर परिस्थिति में विवाह निभाने की सलाह देते हैं, वही समाज कुछ समय संवेदना व्यक्त करने के उपरांत मौन हो जाता है। न तो सामाजिक प्रतिष्ठा उस बेटी का जीवन लौटा सकती है और न ही सामाजिक स्वीकृति उसके खोए हुए सम्मान और अस्तित्व की भरपाई कर सकती है।

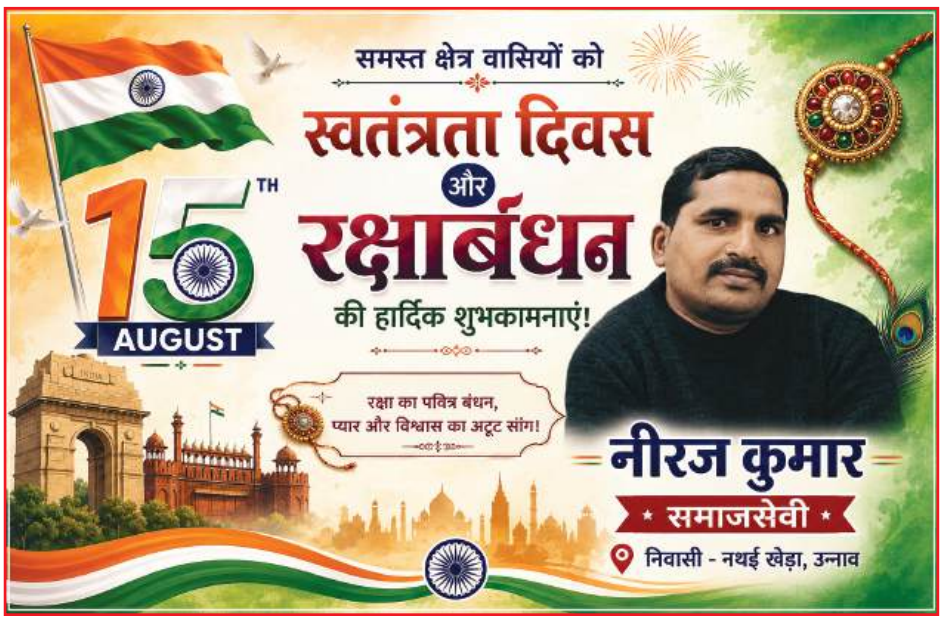

देशभक्ति की बही बयार, शान से लहराया तिरंगा

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

लखनऊ । देश की आजादी का 80वां महापर्व राजधानी में हर्षोल्लास से मनाया गया। सरकारी-गैर सरकारी संगठनों, शिक्षण संस्थानों, सरकारी कार्यालयों में ध्वजारोहण किया गया। सांस्कृतिक कार्यक्रमों में देशभक्ति के तराने गूंजे। तिरंगा यात्राओं में देशप्रेम की झलक दिखी।

राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने जनभवन में ध्वजारोहण किया तथा सलामी ली। उन्होंने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। जन भवन के अधिकारी- कर्मचारियों तथा आदर्श माध्यमिक विद्यालय के विद्यार्थियों द्वारा राष्ट्रगीत 'वंदे मातरम' का सामूहिक गायन किया गया।

उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अजय राय ने नेहरू भवन स्थित प्रदेश मुख्यालय में ध्वजारोहण किया। सेवादल के प्रदेश अध्यक्ष डॉ. प्रमोद कुमार पांडेय ध्वज रक्षक के रूप में मौजूद रहे। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि देश की गंगा-जमुनी तहजीब और एकता-अखंडता को बचाने के लिए संकल्प लेने की आवश्यकता है। सपा व भाजपा के कार्यालयों में भी झंडारोहण हुआ।

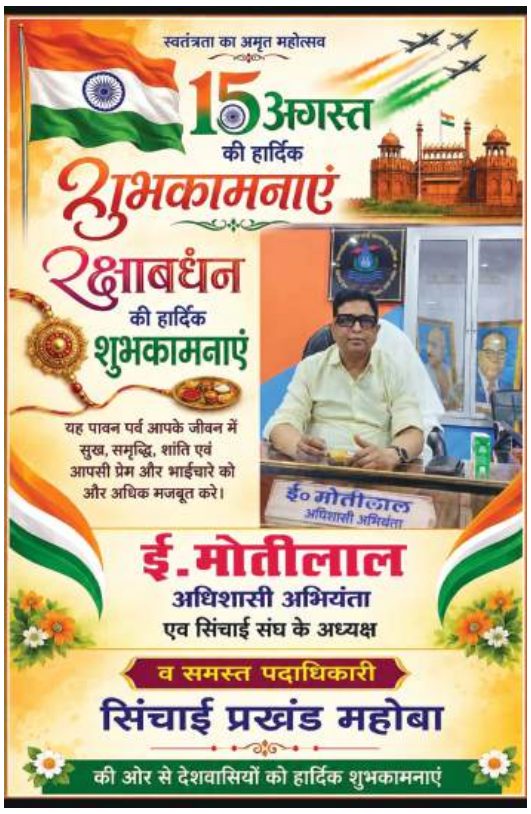

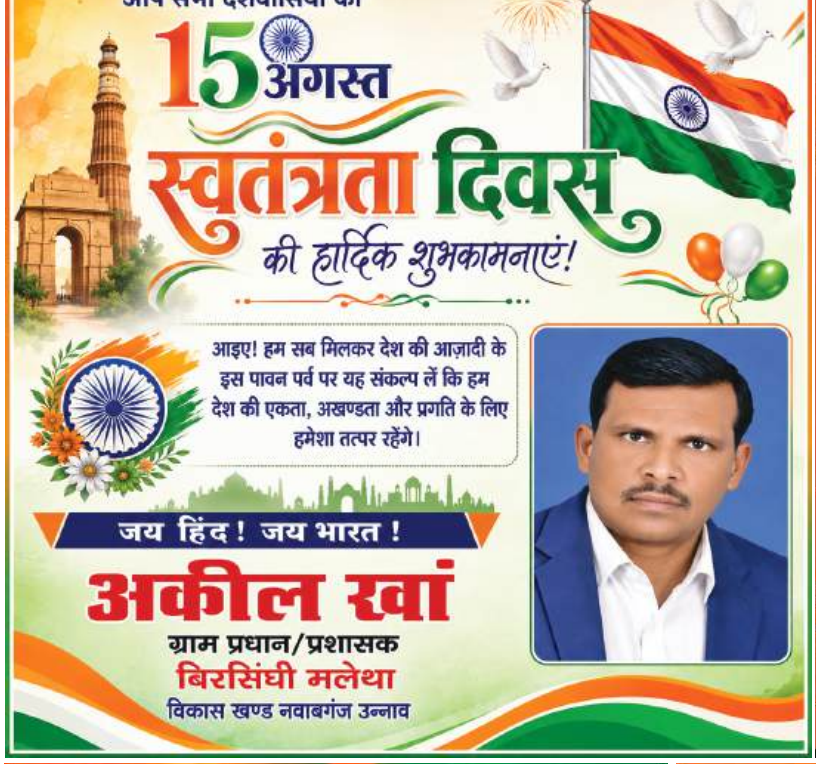

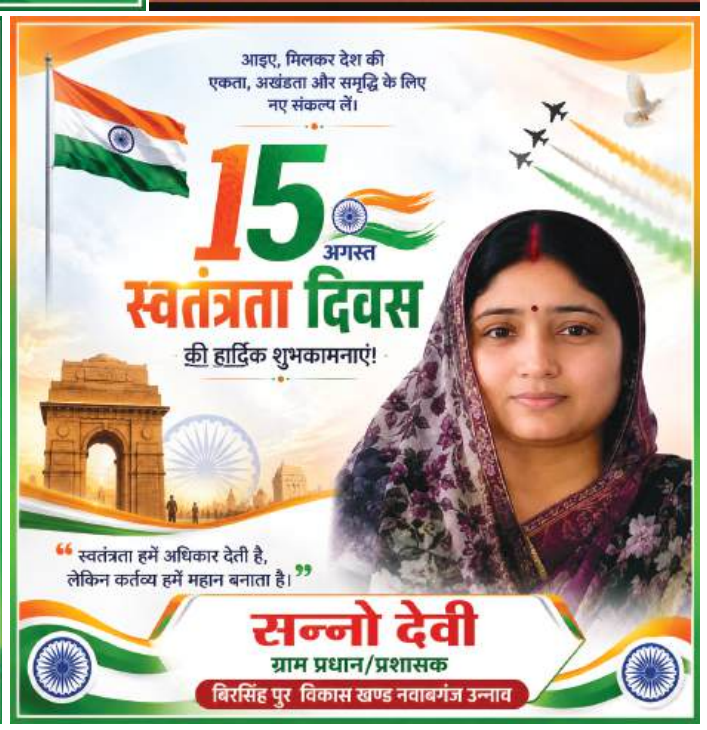

संविधान से ही स्वाधीनता है: अखिलेश यादव

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

लखनऊ। स्वतंत्रता दिवस पर समाजवादी पार्टी के राज्य मुख्यालय, लखनऊ सहित प्रदेश के सभी जनपदों के पार्टी कार्यालयों में राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा शान से फहराया गया। राष्ट्रीय ध्वज को सलामी देने के साथ सभी देशवासियों को बधाई दी गई और अमर शहीदों के सपनों को पूरा करने का संकल्प भी लिया गया।

समाजवादी पार्टी के राज्य मुख्यालय में राष्ट्रीय ध्वज समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव ने फहराया। इस अवसर पर सांसद श्री आर.के चौधरी राष्ट्रीय सचिव राजेन्द्र चौधरी, प्रदेश अध्यक्ष श्याम लाल पाल, पूर्व सांसद अरविन्द कुमार सिंह, प्रदेश कोषाध्यक्ष राज कुमार मिश्रा, पूर्व एमएलसी डॉ. मधु गुप्ता, डॉ. राजपाल कश्यप, रामबृक्ष सिंह यादव, उदयवीर सिंह भी मौजूद रहे।

अखिलेश यादव ने सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि संविधान से ही स्वाधीनता है। आइए हम सब लिकर इस स्वतंत्रता दिवस पर संविधान की रक्षा का संकल्प ले। इसके लिए जो भी त्याग करना होगा, हम करेंगे। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी के प्रदेश मुख्यालय के डॉ. राममनोहर लोहिया सभागार में उपस्थित जन समुदाय एवं मीडिया प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए कहा कि आज के दिन हम राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, सरदार भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और उन तमाम स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को याद कर रहे हैं, जिनकी कुर्बानी, त्याग और बलिदान की वजह से हम सबको आजादी मिली है।

राहुल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत

» आय से अधिक संपत्ति मामले में हाईकोर्ट की सुनवाई रोकी

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट की सुनवाई पर रोक लगा दी है। शीर्ष अदालत ने सीबीआई और ईडी को भी हाई कोर्ट के सामने रिपोर्ट पेश न करने का निर्देश दिया, इस मामले की गहराई से जांच करने का संकेत दिया है। कोर्ट ने कहा कि वह जांच एजेंसियों के काम करने के तरीके पर सवाल उठाने वाले हाई कोर्ट के निर्देशों की समीक्षा करेगा, साथ ही प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों पर जोर दिया।

सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय से कहा कि वह कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक संपत्ति के मामले में कार्यवाही आगे न बढ़ाए। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई और एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को यह भी निर्देश दिया कि वे लोकसभा में विपक्ष के नेता गांधी के खिलाफ मामले के संबंध में हाई कोर्ट के सामने कोई रिपोर्ट पेश न करें। चीफ जस्टिस सूर्य कांत और जस्टिस जॉयमाल्य बागची और वी. मोहना की बेंच ने गांधी की ओर से पेश सीनियर वकील कपिल सिबल की दलीलों पर गौर किया और कर्नाटक के रहने वाले एस. विग्नेश शिशिर (जिन्होंने हाई कोर्ट का रुख किया था) के साथ-साथ सीबीआई और ईडी को भी नोटिस जारी किए। यह बेंच इस मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली गांधी की याचिका पर सुनवाई कर रही थी।

सीबीआई और ईडी को भी नोटिस जारी

मामले की जांच करेगी शीर्ष अदालत

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह इस मामले की जांच करना चाहता है क्योंकि एक अदालत ने निर्देश जारी किए थे, जिससे जांच एजेंसियों के काम करने के तरीके पर सवाल उठे थे। सुनवाई के दौरान, बेंच ने प्राकृतिक न्याय के महत्व पर भी जोर दिया और कहा कि ऐसी कार्यवाही के दौरान अदालतों से निष्पक्षता के सिद्धांतों का पालन करने की उम्मीद की जाती है। जब सीबीआई सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस मामले की जांच करने पर आपत्ति जताई, तो बेंच ने एजेंसी के रुख पर सवाल उठाए। कोर्ट ने कहा कि अगर सीबीआई ने खुद से यह प्रक्रिया शुरू नहीं की थी और हाई कोर्ट के निर्देशों के कारण ऐसा किया था, तो सुप्रीम कोर्ट को उन हालात की जांच करने का अधिकार है जिनमें वे निर्देश जारी किए गए थे।

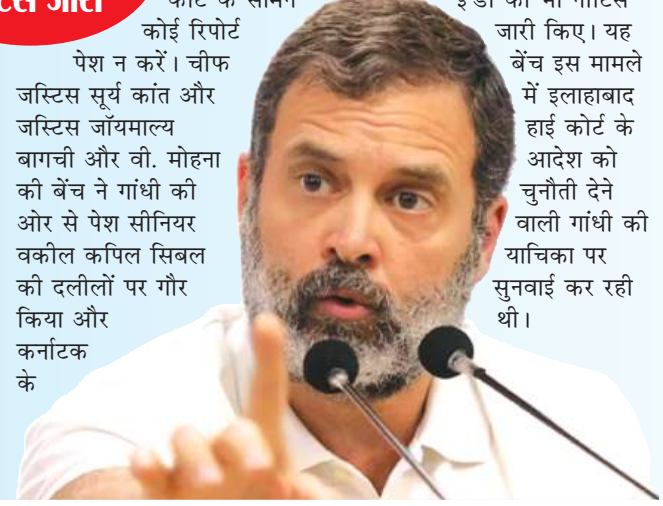

नेता प्रतिपक्ष ने यूजीसी-नेट री-टेस्ट पर पीएम मोदी को घेरा

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सोमवार को नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) के इंजिनिअर, कॉमर्स और सोशियोलॉजी के लिए यूजीसी-नेट परीक्षा दोबारा कराने के फ़ैसले की कड़ी आलोचना की। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि मोदी जी, देखिए आपकी एनटीए ने अभी क्या किया है। उन्होंने कहा कि एजेंसी ने गलत पेपर बनाए और पुराने सवाल दोहराए, जिसकी वजह से हज़ारों उम्मीदवारों को सितंबर में दोबारा परीक्षा देनी पड़ रही है। एक पोस्ट में गांधी ने कहा कि सोशियोलॉजी, इंग्लिश और कॉमर्स के लिए यूजीसी-नेट परीक्षाएं 22 से 30 जून के बीच हुई थीं। लगभग दो महीने बाद, एनटीए ने इन तीनों परीक्षाओं को रद्द कर दिया है क्योंकि उसने गलत पेपर सेट किए थे और पुराने सवाल दोहराए थे। उन्होंने कहा कि जिन हज़ारों उम्मीदवारों ने इन परीक्षाओं की तैयारी की थी, उन्हें अब यह प्रक्रिया फिर से दोहरानी होगी। गांधी ने कहा कि जिन हज़ारों उम्मीदवारों ने सालों तक तैयारी की, फ़ॉर्म भरे, फ़ीस जमा की और दूर-दराज़ के सेंटरों तक यात्रा की, उन्हें अब सितंबर में यह सब फिर से करना होगा। गलती एनटीए करता है, लेकिन सज़ा छात्र को भुगतनी पड़ती है। कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया कि परीक्षा प्रणाली एक शोषण करने वाली मशीन बन गई है। उन्होंने कहा कि यह छात्रों से पैसे, उनके कीमती साल, मानसिक स्वास्थ्य और आत्मविश्वास तो ले लेती है, लेकिन बदले में कुछ नहीं देती। उन्होंने कहा कि मैंने कोटा, देहरादून और प्रयागराज में भी यही बात कही थी और आगे भी कहता रहूंगा - यह अब शिक्षा प्रणाली नहीं रही। यह एक शोषण करने वाली मशीन है।

सुखबीर बादल पर हमले की हाई-लेवल जांच हो: हरसिमरत कौर

» शिअद सांसद को गृहमंत्री शाह को लिखा पत्र

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

चंडीगढ़। शिअद सांसद हरसिमरत कौर बादल ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर सुखबीर सिंह बादल पर हुए दो जानलेवा हमलों की एनआईए जांच की मांग की है। उन्होंने नांदेड़ में 13 अगस्त को हुए हमले और दिसंबर 24 में गोल्डन टेम्पल में जान लेने की कोशिश, दोनों के बीच संभावित बड़ी साजिश और संबंध की गहन पड़ताल का आग्रह किया है, जो पंजाब में राजनीतिक हिंसा पर गंभीर चिंताएं उठाता है। शिअद की सांसद हरसिमरत कौर बादल ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर एनआईए से जांच की मांग की।

यह मांग 13 अगस्त को महाराष्ट्र के नांदेड़ में श्री हजूर साहिब गुरुद्वारे में अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल पर हुए हमले और दिसंबर 24 में गोल्डन टेंपल में उनकी हत्या की कोशिश के मामले में की गई है। सुखबीर बादल की पत्नी हरसिमरत कौर ने अपने पत्र में महाराष्ट्र के नांदेड़ में 13 अगस्त की घटना को हत्या की एक कायराना और घिनौनी कोशिश बताया। उन्होंने घटना की गंभीरता, उसके तरीके और हालात का हवाला देते हुए केंद्र सरकार से इसकी जांच नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी -एनआईए को सौंपने की अपील की। शिअद सांसद ने केंद्र से 13 अगस्त को हुए हमले और 4 दिसंबर, 024 को अमृतसर के गोल्डन टेम्पल में सुखबीर बादल की जान लेने की पिछली कोशिश, दोनों की हाई-लेवल जांच का आदेश देने की मांग की।

महाकाल मंदिर में भगदड़, नागचंद्रेश्वर दर्शन में 13 घायल

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

इंदौर। मध्य प्रदेश के उज्जैन में नागचंद्रेश्वर मंदिर में सोमवार को भीड़ के कारण कम से कम 13 लोग बेहोश हो गए। मंदिर प्रशासन ने बताया कि यह मंदिर साल में सिर्फ़ एक बार नाग पंचमी पर खुलता है, और इस बार यह मौका सावन के तीसरे सोमवार के साथ पड़ने की वजह से भक्तों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। उनके मुताबिक, हरसिद्धि मंदिर के सामने बैरिकेड वाले इलाके में श्रद्धालु इंतज़ार कर रहे थे, जिससे वहां भीड़ जमा हो गई।

अधिकारियों ने बताया कि बैरिकेड वाले इलाके में एक ट्रांसफॉर्मर के पास बिजली का करंट लीक होने की अफवाह फैलने से अफ़रा-तफरी मच गई। अधिकारियों ने बताया कि 13 लोगों को ज़िला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। डॉक्टरों के अनुसार, वे कड़ी निगरानी में हैं। मौके पर मौजूद पुलिस और प्रशासन के कर्मचारियों ने स्थिति को काबू में किया। घायल श्रद्धालुओं में से एक, जिसकी पहचान सागर के तौर पर हुई है, ने बताया कि हरसिद्धि चौराहा पहुंचने से पहले वह महाकाल मंदिर में कई घंटों तक लाइन में खड़ा रहा था। सागर ने समाचार एजेंसी को बताया कि मैं महाकाल मंदिर में दर्शन के लिए लाइन में लगा था। 7-8 घंटे बाद मैं हरसिद्धि चौराहे पर पहुंचा। हम वहां 2 घंटे तक खड़े रहे। भीड़ बढ़ती जा रही थी और आरती का समय होने के कारण हमें वहीं रोक दिया गया।

नगर निगम पुलिस टीम पर पथराव

» दारोगा को जंजीर से पीटा सिर में लगे छह टांके

» पारा में डेयरी कार्रवाई के दौरान बवाल

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

लखनऊ। पारा क्षेत्र में डेयरी संचालकों के खिलाफ कार्रवाई करने पहुंची नगर निगम और पुलिस की संयुक्त टीम पर अचानक पथराव से हमला देखते ही देखते मौके पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया। हमले में बुद्धेश्वर चौकी प्रभारी दारोगा विनय पटेल समेत नगर निगम टीम के कई कर्मचारी घायल हो गए। हमलावरों ने कई वाहनों में भी तोड़फोड़ की। बताया जा रहा है कि कार्रवाई के दौरान टीम ने डेयरी संचालकों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की, जिसका कुछ लोगों ने विरोध किया। इसी दौरान अचानक पथराव शुरू हो गया।

आरोप है कि हमलावरों ने बुद्धेश्वर चौकी प्रभारी विनय पटेल को दौड़ाकर पीटा और उन पर जंजीर से हमला किया। हमले में दारोगा के सिर में गंभीर चोट आई और उन्हें छह टांके लगाए गए। घटना में नगर निगम टीम में शामिल अवधेश कुमार, अभिनव और फुरकान के भी घायल हुए चोटे आई है। जोन-6 के प्रभारी पशु कल्याण अधिकारी अवधेश कुमार की ओर से पारा थाने में तहरीर दी गई है।

15 नामजद समेत 12 अज्ञात पर एफआईआर

पुलिस ने मामले में 15 नामजद और 12 अज्ञात आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। पुलिस अब आरोपियों की पहचान और गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई कर रही है। पशु कल्याण अधिकारी डॉ. अभिनव वर्मा के मुताबिक, टीम डेयरी संचालकों के खिलाफ कार्रवाई करने पहुंची थी। कार्रवाई शुरू होते ही कुछ लोगों ने विरोध किया और देखते ही देखते टीम पर पथराव कर दिया। घटना के बाद मौके पर पुलिस बल तैनात किया गया।

तार्किक परिणाम तक पहुंचाएं : सीजेआई

» राम मंदिर चंदा चोरी पर सीजेआई की अहम टिप्पणी

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

नई दिल्ली। राम मंदिर चंदा चोरी केस में सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई हुई। सीजेआई सूर्यकांत ने कहा है कि जांच को तार्किक परिणाम तक पहुंचाने का प्रयास करें। सीजेआई ने पूछा कि जांच में कितना समय लगेगा? इसपर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि 3 सप्ताह बाद सुनवाई करें।

सॉलिसिटर ने कहा कि एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट कोर्ट को दी है। एसआईटी अध्यक्ष यहां मौजूद हैं। वहीं निर्मोही अखाड़े के वकील ने कहा कि हमारी भी एक याचिका है। उसे लिस्ट नहीं किया गया है। सीजेआई ने कहा कि आप भी बेहतर जांच चाहते हैं? हम आपको सुनेंगे। इसके बाद वकील ने कहा कि हम यह भी कह रहे हैं कि कोर्ट के जजमेंट का पूरी तरह पालन हो।

कंगारूओं को 9 विकेट से हराकर बांग्लादेश ने रचा इतिहास

» 30 वर्षों में ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट जीतने वाली बनी दूसरी एशियाई टीम

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

डार्विन। बांग्लादेश ने रविवार को ऑस्ट्रेलियाई धरती पर ऐतिहासिक टेस्ट मैच जीतकर इतिहास रच दिया। नजमुल हुसैन शांतो की कप्तानी वाली टीम ने डार्विन के माराारा क्रिकेट ग्राउंड में खेले गए दो मैचों की टेस्ट सीरीज के पहले मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया को नौ विकेट से हराकर सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली। यह पहली बार है जब बांग्लादेश ने ऑस्ट्रेलिया को उसी की धरती पर टेस्ट मैच में हराया है। पहली पारी में 228 रनों की मजबूत बढ़त हासिल करने के बाद बांग्लादेश ने दूसरी पारी में ऑस्ट्रेलिया को 284 रन पर समेट दिया, जिससे उनके सामने जीत के लिए मात्र 57 रनों का आसान लक्ष्य रह गया।

हालांकि उन्होंने पहली पारी के शतकवीर तंजिद हसन तमीम को पांच गेंदों पर बिना खाता खोले खो दिया, लेकिन मेहमान टीम ने सिर्फ 14.2 ओवरों में और केवल एक विकेट गंवाकर आसानी से लक्ष्य हासिल कर लिया। बांग्लादेश के लिए यह जीत ऐतिहासिक है क्योंकि उसने इससे पहले कभी कंगारू टीम को ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट में नहीं हराया था।

इस ऐतिहासिक जीत के साथ बांग्लादेश पिछले 30 वर्षों में भारत के बाद ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट मैच जीतने वाली केवल दूसरी एशियाई टीम बन गया है। इससे पहले, ऑस्ट्रेलिया में पाकिस्तान की आखिरी टेस्ट जीत नवंबर-दिसंबर 1995 में आई थी। इस तरह बांग्लादेश सबसे तेजी से ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट मैच जीतने वाली एशियाई टीम बन गई है। पाकिस्तान ने अपने सातवें प्रयास में ऑस्ट्रेलिया में अपनी पहली टेस्ट जीत हासिल की थी, जबकि भारत को ऑस्ट्रेलियाई धरती पर अपनी पहली जीत दर्ज करने के लिए 12वें टेस्ट तक का इंतजार करना पड़ा था। दूसरी ओर, बांग्लादेश ने यह उपलब्धि ऑस्ट्रेलिया में अपने केवल तीसरे टेस्ट में ही हासिल कर ली। सिर्फ इंग्लैंड ने ही बांग्लादेश से कम मैचों में ऑस्ट्रेलियाई धरती पर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपनी पहली टेस्ट जीत हासिल की है।

हार के बाद भी अंक तालिका में शीर्ष पर बरकरार ऑस्ट्रेलिया

नई दिल्ली। इस मैच में हार के बावजूद विश्व टेस्ट चैंपियनशिप (डब्ल्यूटीसी) की अंक तालिका में ऑस्ट्रेलिया का दबदबा बरकरार है और वह शीर्ष पर मौजूद है। हालांकि, पीसीटी के तहत दूसरे स्थान पर मौजूद दक्षिण अफ्रीका से ऑस्ट्रेलिया का फासला कम हो गया है। इस ऐतिहासिक जीत का फायदा बांग्लादेश को हुआ है। बांग्लादेश के अब 40 अंक हो गए हैं, फिलहाल डब्ल्यूटीसी की अंक तालिका में चौथे स्थान पर है। भारत पांचवें स्थान पर है और उसकी पीसीटी 48.15 प्रतिशत है। भारत वॉल टेस्ट जीतने में सफल रहा तो भी वह डब्ल्यूटीसी की अंक तालिका में फिलहाल पांचवें स्थान पर ही रहेगा। वहीं, श्रीलंका अगर पहला टेस्ट जीतने में सफल रहा तो उसकी पीसीटी 53.33 प्रतिशत हो जाएगी और वह भारत से आगे निकल जाएगा। भारत और श्रीलंका के बीच पहला टेस्ट अगर ड्रॉ पर समाप्त होता है तो दोनों टीमों की डब्ल्यूटीसी अंक तालिका में परिवर्तन नहीं होगा।

फिल्म 'सहिया' के समर्थन में उतरे खास से आम लोग

» निर्माता-निर्देशक के लिए सोशल मीडिया में उभरे स्वर

» सरकार व सेंसर बोर्ड पर लोगों ने उठाए सवाल

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

नई दिल्ली। फिल्म सहिया की स्क्रीनिंग में देरी पर आम से लेकर खास लोगों ने सरकार व केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए है।

सोशल मीडिया में फिल्म और निर्माता निर्देशक के समर्थन की बाढ़ आ गई है। सब लोग ऐसा लग रहा है सहिया की बहिया थामने को बेताब हैं। सभी एक सुर में उसको तुरंत प्रमाणन देने की मांग कर रहे हैं। लोगों को कहना है कि एक प्रेम कहानी को सरकार सबको देखने दे।

"सहिया' एक ऐसी फिल्म लग रही है, जिसका इंतजार किया जा सकता है। झारखंड के नेतरहाट की खूबसूरत वादियों में बनी यह फिल्म एक पारिवारिक और मानवीय प्रेम कहानी है। नीरज काबी, शांतनु माहेश्वरी और रिंकू राजगुरु जैसे शानदार कलाकार इसमें नजर आएंगे। फिल्म के संगीत और गीतों में स्वानंद किरकिरे जैसे बेहतरीन कलाकार का जुड़ना इसे और खास बनाता है। लेकिन सेंसर प्रक्रिया में हो रही देरी पर सवाल उठना भी जरूरी है। अगर फिल्म में नक्सलवाद का प्रचार नहीं है, तो फैसला जल्द और साफ तरीके से होना चाहिए। अच्छी कहानी को दर्शकों तक पहुंचने का मौका मिलना चाहिए। 'सहिया' का इंतजार है।

रागा फॉर इंडिया

फिल्म इंडस्ट्री समय से चलती है। रिलीज डेट, थिएटर, प्रमोशन, ओटीटी डील - सब एक कैलेंडर पर निर्भर है। सहिया की डेढ़ महीने की देरी ने वो पूरा कैलेंडर बिगाड़ दिया। अब न पुरानी प्लानिंग काम की, न नया बजट। इसका खामियाजा सिर्फ निर्माता नहीं, बल्कि स्वानंद किरकिरे समेत पूरी टीम भुगत रही है।

रितेश देशमुख

हर दिन की देरी का मतलब है ब्याज का बढ़ना, कर्ज का बढ़ना, और उम्मीदों का टूटना। साहिया के निर्माताओं ने अपनी पूरी पूंजी इस फिल्म में लगाई है। लेकिन रिलीज न होने के कारण रिकवरी रुकी हुई है। क्या सरकार और सीबीएफसी इस आर्थिक नुकसान की भरपाई करेंगे? या फिर फिल्ममेकर को खुद ही इस लड़ाई को लड़ना होगा?

अंशु पटेल

हम अक्सर कहते हैं कि रीजनल सिनेमा को बढ़ावा मिलना चाहिए। सहिया उसी दिशा में एक कदम थी। झारखंड की कहानी, झारखंड की लोकेशन, झारखंड के कलाकार। लेकिन जब ऐसी फिल्में ही सिस्टम में उलझ जाएंगी तो नए फिल्ममेकर हिम्मत कैसे करेंगे? संजय शर्मा आज अकेले नहीं लड़ रहे, वो पूरी इंडस्ट्री की आवाज बन गए हैं।

कल्पना

सीबीएफसी का काम फिल्मों को प्रमाणित करना है, उन्हें रोकना नहीं। लेकिन सहिया के केस में लग रहा है कि प्रक्रिया ही सबसे बड़ी बाधा बन गई है। न कोई कारण बताया जा रहा है, न कोई समय-सीमा। फिल्ममेकर अंधेरे में हैं। अगर एक प्रियोरिटी फिल्म के साथ ऐसा हो सकता है तो फिर सिस्टम पर भरोसा कैसे करें?

ललित ज्याणी

फिल्म इंडस्ट्री में टाइमिंग सब कुछ होती है। फेस्टिवल डेट, छुट्टियां, थिएटर की उपलब्धता - सब पहले से तय होता है। सहिया की डेढ़ महीने की देरी ने पूरी मार्केटिंग और रिलीज प्लान बिगाड़ दिया। अब न पुरानी डेट काम की, न नया प्रमोशन। इसका सीधा असर फिल्म के बिजनेस और टीम के मनोबल पर।

दीना देवी

नेतरहाट को राष्ट्रीय स्क्रीन पर लाने का मौका सहिया के पास था। झारखंड की संस्कृति, प्रकृति और लोगों की कहानी देश देख सकता था। स्वानंद किरकिरे की आवाज से सजी इस फिल्म को प्रक्रिया की सुस्ती ने रोक दिया। क्या हम रीजनल सिनेमा की बात करते हुए उसकी रिलीज को ही अटका देंगे?

निधि

निर्माता संजय शर्मा के अनुसार, स्क्रीनिंग के दौरान फिल्म को नक्सलवाद की पृष्ठभूमि के कारण रिव्यू कमेटी में भेजे जाने की बात कही गई। उनका स्पष्ट कहना है कि सहिया नक्सलवाद पर आधारित फिल्म नहीं, बल्कि झारखंड के जंगलों की पृष्ठभूमि में बुनी गई एक पारिवारिक और मानवीय प्रेम कहानी है। फिल्म में किसी हिंसक विचारधारा या नक्सलवाद का समर्थन नहीं किया गया है।

संदीप चौधरी कमेंट्री

केआरके साहिया के पक्ष में उतरे

केआरके (कमाल आर खान) ने **4PM** न्यूज नेटवर्क के संस्थापक संजय शर्मा की फिल्म सहिया और सेंसर बोर्ड (सीबीएफसी) के विवाद पर सोशल मीडिया (एक्स/ट्विटर) पर यह टिप्पणी की कि सेंसर बोर्ड ने फिल्म को सीधे सर्टिफिकेट देने से मना कर दिया है और इसे रिव्यू कमेटी के पास भेज दिया है। केआरके के अनुसार, सेंसर बोर्ड का यह आरोप है कि इस फिल्म में कथित तौर पर नक्सलियों को बढ़ावा दिया जा रहा है या उनका समर्थन किया जा रहा है, जबकि फिल्म के निर्माता-निर्देशक संजय शर्मा ने इन आरोपों को पूरी तरह खारिज किया है। केआरके ने दावा किया कि फिल्म रिलीज के लिए तैयार थी, लेकिन सीबीएफसी ने इसे अनुमति देने के बजाय समीक्षा समिति को सौंप दिया। केआरके की पोस्ट के मुताबिक, फिल्म पर यह सवाल उठाया गया है कि इसकी कहानी में नक्सली समस्याओं को इस तरह दिखाया गया है जिससे वे प्रोत्साहित होते हैं।

'सहिया' की रिलीज अटकी?

CBFC की प्रतिक्रिया पर फिल्ममेकर संजय शर्मा ने उठाए सवाल फिल्म सहिया के निर्माता-निर्देशक संजय शर्मा ने सीबीएफसी पर सर्टिफिकेशन प्रक्रिया में देरी का आरोप लगाया है उनका कहना है कि फिल्म नक्सलवाद पर आधारित नहीं है।

संजय शर्मा ने साफ कहा है कि सहिया नक्सल फिल्म नहीं है। फिर भी इसे लेकर जो लापरवाही बरती जा रही है वो समझ से परे है। प्रियोरिटी कैटेगरी का मतलब होता है तेजी। लेकिन यहां तो न स्क्रीनिंग समय पर हुई, न फैसला। अगर यही हाल प्रियोरिटी का है तो नारमल कैटेगरी की फिल्मों का क्या होता होगा? सिस्टम में पारदर्शिता और जवाबदेही लाना अब बहुत जरूरी हो गया है।

रियल इंडिया वायस

सवाल सिर्फ सहिया का नहीं है। सवाल प्रक्रिया का है। प्रियोरिटी में 7 दिन में स्क्रीनिंग, 15 दिन में फैसला- ऐसा नियम क्यों नहीं बन सकता? क्यों हर फिल्ममेकर को महीनों तक दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ते हैं? संजय शर्मा ने आवाज उठाई है, उम्मीद है अब सिस्टम सुनेगा।

पांडियान

फिल्म सहिया की सेंसर प्रक्रिया में हो रही देरी पर निर्माता-निर्देशक संजय शर्मा ने सीबीएफसी की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि फिल्म के लिए प्रियोरिटी श्रेणी में आवेदन किया गया था, लेकिन निर्धारित समय-सीमा के बजाय करीब डेढ़ महीने बाद स्क्रीनिंग हुई।

मनमोहन सिंह, कमेंट्री

प्रायोरिटी कैटेगरी (प्राथमिकता श्रेणी) के तहत आवेदन करने वाली एक फिल्म को हफ्तों की देरी के बाद भी सर्टिफिकेशन का इंतजार है। अगर कोई आपत्ति है, तो उसे नियमों के दायरे में रहकर और पारदर्शी तरीके से सुलझाया जाना चाहिए, न कि अंतहीन इंतजार करवाकर। फिल्ममेकर्स एक निष्पक्ष और समय-सीमा के भीतर होने वाली सर्टिफिकेशन प्रक्रिया के हकदार हैं।

महुआ मोइत्रा, फैन्स

लड़ाई समय की है

प्रोड्यूसर और डायरेक्टर संजय शर्मा कि शिकायत को सिर्फ फिल्म को सेंसर ने रोक दिया के रूप में देखना शायद इस कहानी को छोटा कर देना होगा। असल संकट समय का है फिल्म की रिलीज रणनीति समय पर टिकी होती है मार्केटिंग समय पर टिकी होती है थिएटर समय पर मिलते हैं कलाकारों की उपलब्धता भी समय पर निर्भर करती है और पैसा भी समय के साथ खर्च होता है। इसलिए अगर रिलीज प्रक्रिया में देरी होती है तो नुकसान सिर्फ एक तारीख का नहीं होता। नुकसान पूरी रिलीज स्ट्रेटेजी का होता है।

सहिया एक मानवीय कहानी है। इसमें नफरत नहीं, प्रेम है। इसमें हिंसा नहीं, रिश्ते हैं। ऐसी फिल्मों की आज सबसे ज्यादा जरूरत है। लेकिन दुर्भाग्य है कि ऐसी फिल्म ही सिस्टम की सुस्ती का शिकार बन गई। अगर हम अच्छी कहानियों को समय पर दर्शकों तक नहीं पहुंचाएंगे तो फिर सिनेमा का भविष्य क्या होगा?

वर्मा जी

संजय शर्मा अकेले नहीं हैं। हर साल सैकड़ों फिल्ममेकर सीबीएफसी की धीमी प्रक्रिया से जूझते हैं। साहिया सिर्फ एक उदाहरण है। स्वानंद किरकिरे जैसे प्रतिष्ठित कलाकार भी इस देरी से प्रभावित हैं। इसलिए इस मुद्दे को गंभीरता से लेना जरूरी है।

अकरम

सिनेमा सिर्फ मनोरंजन नहीं है, ये एक उद्योग है। इसमें पैसा लगता है, समय लगता है और सैकड़ों लोगों की रोजी-रोटी जुड़ी होती है। सहिया के साथ भी यही हुआ। शूटिंग नेतरहाट में हुई, पोस्ट प्रोडक्शन पूरा हुआ, प्रमोशन की प्लानिंग बनी। लेकिन सीबीएफसी की सुस्त प्रक्रिया ने सब रोक दिया। प्रियोरिटी में जमा करने के बाद भी 45 दिन बाद स्क्रीनिंग और अब महीनों से कोई अपडेट नहीं। संजय शर्मा का सवाल जायज है - अगर सिस्टम खुद अपने नियमों का पालन नहीं करेगा तो फिल्ममेकर किस पर भरोसा करेंगे?

सौरभ बक्शी

महाराष्ट्र कार्यालय:- 4पीएम न्यूज़ नेटवर्क, 2-डी सिटी मॉल, अंधेरी वेस्ट, मुंबई, महाराष्ट्र - 400053। विधि सलाहकार: मोहम्मद हैदर
*इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी।
RNI-UPHIN/2015/62233, दूरभाष: 0522- 4078371 | Email: daily4pm@gmail.com | website: www.4pm.co.in |
समस्त विवाद लखनऊ न्यायालय के अधीन ही होंगे।

स्वामी 4 पीएम न्यूज नेटवर्क्स प्राइवेट लिमिटेड के लिए
मुद्रक एवं प्रकाशक संजय शर्मा
द्वारा आस्था प्रिंटर्स, 5/600, विकास खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ-226010 (यूपी) से मुद्रित
पता 5/600, विकास खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ-226010 (यूपी) से प्रकाशित। संपादक- संजय शर्मा